

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक ~~३६८४~~ / 36सी.

दिनांक रानीखेत अक्टूबर ०१, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग।
(प्रस्ताव संख्या 9017 / 2014)

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक मैमो / 12-1(2) दिनांक 29.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	The village level committee proceeding for village Kunjhana is still not provided by the State Govt. May provide the same.	The village level committee proceeding for village Kunjhana FRA is submitted in K part I
2.	The hard copy of the proposal is not provided to this office yet. The state Govt. may provided hard copy of the proposal to this office.	Hard copy submitted in Nodal office Dehradun by letter no. 1883/36c dated 06-08-2016. (Letter Attached)


 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
११८ रानीखेत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679

Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1883 / 36सी.

दिनांक रानीखेत अगस्त 6, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा कालोनी, फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा में इस खण्ड के अधीन विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस खण्ड द्वारा विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किये गये हैं, जिनकी हार्ड कापी आपके कार्यालय में प्रस्तुत की जा रही है।

1. जनपद अल्मोड़ा में ईकुखेत—गुदलेख—मसमोली मोटर मार्ग का निर्माण। (7.290हौ) (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/16209/2015)
2. जनपद अल्मोड़ा के विधान सभाक्षेत्र सल्ट में मंगरौखाल—तनसालीसैण—कालिंकाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (8.280हौ) (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/16180/2016)
3. जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में सरपटा—चुनली—कोटा—बासोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (0.537हौ) (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9017/2014)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 3-3 प्रतियों में।

भवदीय,

एम/ए

(कुन्दन लाल वर्मा)

अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

रानीखेत।

पत्रांक 1883 / 36सी 6/8/16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

०/८

16/8/16

अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

रानीखेत।

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

स्थापना - चंद्रुली - कोटा - जामोट भोटे झारी
पीपलगांव वैष्ण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चंद्रुली
तहसील चंद्रुली जिला उत्तराखण्ड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद काशी के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परियोजना के निर्माण हेतु (10.53) हेतु आरक्षित वन भूमि, 10.53 हेतु सिविल सोयम भूमि 10.21 हेतु, वन पंचायत भूमि 10.287 हेतु) अर्थात् कुल 10.53 हेतु वन भूमि का 10.110 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चंद्रुली द्वारा दिनांक 8-11-2014 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा चंद्रुली सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चंद्रुली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.110 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/-
ग्राम सचिवहो/-
ग्राम प्रधान

प्रधान

ग्राम पंचायत-चंद्रुली

विधायक सभा (अल्पोड़ा)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कुर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्राम प्रधान

ग्राम सभा-चंद्रुली
विधायक सभा अल्पोड़ा
जिला-उत्तराखण्ड, उत्तरांचल

1.6 B

प्रपत्र-23.1

दिनांक 5/11/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत वारुडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श/वलीराहा शुरुराम
2	ल.ज.नाथ ल.नाथ
3	जगन्नाथ जगन्नाथ
4	पंडित श. गोप्ता
5	देवेन्द्र श. गोप्ता नाथ
6	देवेन्द्र श. वारुडा
7	विजयराम श. वारुडा
8	उमापाति श. सराम ह.
9	श/प. देवी अपाति वर्मा
10	मीनांकी ल.लालपाति
11	देवेन्द्र श. उमापाति
12	काशीराम श. ल.राम
13	व-देवराम श. ल.राम
14	बुमिपाति ल.राम
15	आमराति ल.राम आमराति
16	उमापाति ल.राम डामराति
17	ल.राम ल.राम
18	ल.राम ल.राम
19	ल.लंबाति ल.राम
20	ल-द-राम ल.राम

(१) श/माला श. ए. ए. ए. ए. = कवालिटि

(२) देवकी देवी श. ल.राम देवकी देवी

(३) गोदारी देवी श. ल.राम गोदारी देवी

वालमाति ल.राम वालमाति ल.राम

(४) नरेन्द्र श. ल.राम नरेन्द्र ल.राम

मानवी देवी ल.राम ल.राम

ह0/-

ग्राम प्रधान

देवेन्द्र श.राम
प्रधान

ग्राम पंचायत-चनुली
विधायक सभा (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

झनपट अल्मोड़ा में सरपटा - चनुली - कोटा - बीसोहर
झो. मणि का नव निर्गाण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सरपटा / चनुली
तहसील रामरेत जिला झनपटा

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद झनपटा के अन्तर्गत सरपटा - चनुली - कोटा - बीसोहर परियोजना के निर्माण हेतु (.....
..... हेतु आरक्षित वन भूमि हेतु सिविल सोयम भूमि 0.252 हेतु वन पंचायत भूमि 0.287 हेतु) अर्थात कुल 0.537.
हेतु वन भूमि का लोटीर्फी विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तूत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सरपटा / चनुली द्वारा दिनांक 4-11-14 को सम्बन्ध ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्टि किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इन्हन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सरपटा / चनुली के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोटीर्फी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई ज्ञापति नहीं है।

द्वितीयांशु
प्रधान
ग्राम पंचायत - चनुली
विभाग नियासैन (अल्मोड़ा) सरपटा
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित प्रधान
21.11.2014
01-06-2015

प्रारूप -23.1

दिनांक 11-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सरपटो-चनुली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मुमुक्षु	गर्भि कुवरसिंह ग्रामीणी दुणिदेवी
2-	दुर्गादेवी	ग्रामीणी
3.	शिवसिंह	ग्रामीणी
4-	कृष्णलालसिंह	॥ कृष्णलालसिंह
5.	दिव्या वामपात्री	॥ दिव्या वामपात्री
6	दिव्या गाड़ी	॥ दिव्या गाड़ी

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत सरपटो-चनुली

प्रधान

ग्राम पंचायत-चनुली
विजय शिवासीन (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद - अल्मोड़ा में सरपटा - चलुली - कोटा ग्रामों में
भाजि का नव निर्माण (०.५३७ हेक्टर)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दुनोली
तहसील मिर्कियासैन जिला उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परियोजना के निर्माण हेतु ()
हेतु आरक्षित वन भूमि हेतु सिविल सोयम भूमि 0.250 हेतु वन पंचायत भूमि 0.287 हेतु) अर्थात् कुल 0.537
हेतु वन भूमि का करो करो विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तूत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुनोली द्वारा दिनांक 4-11-04 को सम्बन्ध ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के पाविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुनोली के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्राप्ति हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

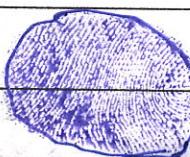
ग्राम पंचायत का नियमित
वार्षिक विवरण
प्रकाश कानून प्रियाली

Pm
ग्राम प्रधान / संपर्क
महार सहित नोली
विंखो-मिर्कियासैन (अल्मोड़ा)

प्रारूप -23.1

दिनांक 4-11-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत इनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दीनान लैंड	दीनान लैंड
	किशनानंद	किशनानंद
	प्रभाग लैंड	प्रभाग लैंड
	दामोदर	दामोदर
	ननदन गिरी	ननदन गिरी
	मधुली केवी	मधुली केवी



मधुली केवी

ग्राम प्रधान / सरपंच

Pc in
प्रधान

ग्राम पंचायत इनोली
विधायिका सेन (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

उत्तरपश्च-अल्मोड़ा में सरपटा - छलुड़ी - कोटा ग्राम पंचायत में
भारी का वह निष्ठा (०.५३७ हेक्टर)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुमारगढ़ा / इनोली
तहसील मुमुक्षुली जिला उत्तरपश्च
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तरपश्च में जनपद कुमारगढ़ा के अन्तर्गत कुमारगढ़ा परियोजना के निर्माण हेतु (X)

..... हेतु आरक्षित वन भूमि X हेतु सिविल स्नोथम भूमि ०.२५ हेतु वन पंचायत भूमि ०.२८७ हेतु) अर्थात् कुल ०.५३७ हेतु वन भूमि का ०.२८७ विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्त्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तूत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमारगढ़ा द्वारा दिनांक ५-११-०६ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत अध्यार्थ की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के पांचिंगों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमारगढ़ा / इनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कुमारगढ़ा को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत
महाराजा बिकिंयासैन
प्रयोक्ता एजेन्सी

Pm
ग्राम प्रद्वान / सरपंच
ग्राम पंचायत सहित नोली १
विभाग-भिकिंयासैन (अल्मोड़ा)

प्रारूप -23.1

दिनांक 4-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत

कुण्डली / इनोली

संख्या	ग्राम पंचायत चार्ट को ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कुमुदा लिंद	कुमुदा लिंद
2.	जमन लिंद	जमन लिंद
3.	मधु लिंदी	मधु लिंदी
4.	रविमला लेवी	रविमला लेवी
5.	कुन्दन लिंद	कुन्दन लिंद

ग्राम पंचायत / सरपंच
प्रधान
Clin

ग्राम पंचायत इनोली
विख्याति भिकियासैन (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपट अल्मोड़ा में सम्पदा - चमुली - कोटा - वास्ट ग्रोव
भारी ता जब निर्माण १०.५३७ हेक्टर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सौर
तहसील अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रुपोत्तर परियोजना के निर्माण हेतु (X)

X हेतु आरक्षित वन भूमि X हेतु सिविल सोयम भूमि ०.२८८ हेतु वन पंचायत भूमि ०.२८८ हेतु) अर्थात कुल ०.५३७ हेतु वन भूमि का ०.००७ एक विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत २०१२ द्वारा दिनांक १२/११/१४ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम २०१२ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ०.००७ हेक्टर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रधान
ग्राम पंचायत सौर
शिखर शिक्षियासैन (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत सौर
शिखर शिक्षियासैन (अल्मोड़ा)
मुहर सहित

सरपंच का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में सुरपटा - चटुकी - कोटा - लासोट
कोटा मार्ग
का..... नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 02-11-014 को ग्राम पंचायत सुरपटा की बैठक आहूत की गयी, जिसमें सुरपटा - चटुकी - कोटा - लासोट मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन पंचायत सुरपटा की भूमि व वृक्ष प्रभावित होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मार्ग का निर्माण शीघ्र कर लिया जाय।

✓
सदस्य

1. दुण्डा देवी
2. पता/पाल्या
3. शान्ती देवी
4. म.का.संस्कृती देवी
5. रघुमार्हा

✓
सरपंच

Kheem Singh
सरपंच
वन पंचायत सीरे
निःख ख० भिकियारेन (अल्मोड़ा)

दिनांक 2-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सौर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	बोगाईं हुंड ५१० इन्द्रियां	बोगाईं हुंड
2.	राजोईं हुंड ५१० वन्दीं हुंड	राजोईं हुंड
3.	शंजोइं हुंड ५१० हरी बांध	शंजोइं हुंड
4.	आम्बा देवी ५१० चन्द्रा इलह	आम्बा देवी
5.	शमीं हुंड ५१० आमीं हुंड	शमीं हुंड
6.	देव मीं हुंड ५१० कुतमीं हुंड	देव मीं हुंड

प्रधान । । । । । ।
ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत सौर
३०५० भिकियासेण (अल्मोड़ा)
Kheem Singh
सरपंच
ग्राम पंचायत तीरे
३०५० भिकियासेण (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद - सुल्तानपुर में सरपटा - चबुली - लोटा - वास्टर भोटर
मार्ग का नव निर्माण (०.५३७ हेक्टर)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोटा ग्राम पंचायत
तहसील भिजया सरा जिला लखनऊ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत सुल्तानपुर परियोजना के निर्माण हेतु (.....)

X हेतु आरक्षित वन भूमि ०.१८८ हेतु सिविल सोयम भूमि ०.२८७ हेतु वन पंचायत भूमि ०.२८७ हेतु) अर्थात कुल ०.६५२ हेतु वन भूमि का कोटा ग्राम पंचायत विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक १-१-१६ को सम्बन्ध ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के ग्रामियाओं के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटा ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कोटा ग्राम पंचायत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत
वन भूमि
कोटा ग्राम पंचायत

कोटा ग्राम पंचायत
ग्राम प्रधान / सरपटा
ग्राम पंचायत
मुहर सहित
प० - कोटा ग्राम पंचायत
५० ५० चिकियामैन (कल्मोह)

दिनांक 4-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत नं/ट गिवाई

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रैकी कुमुरी	रवली देवी
2-	राणा देवी	राधा देवी
3-	लीला देवी	लीला देवी
4-	जीवन शिंदे	जीवन शिंदे

ग्राम प्रधान / सरपंच

वृक्षप्रिया

ग्राम पंचायत कोषटागियाँ
#0 प्रियासेन (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :— सरपटा-चुड़ाली, कोटा-सलौनी, पीपलगांव बैठक तक लिंक भार्गव

कार्यालय उप जिलाधिकारी, २५/८/२०१४

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

जी. एस. बिष्ट
सदस्य जिला पंचायत
24 बिनोली मिक्यासेण
जिला अल्मोड़ा

उपखण्ड स्तरीय समिति, २५/८/२०१४

उपखण्ड परिषेत्र के अन्तर्गत ३०८०८

(हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.५३७ हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील २५/८/२०१४) की दिनांक ३-११-०१६ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 स्वं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री २५/८/२०१४-१०/८/२०१४ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उप जिलाधिकारी,

विकास सेण (पत्रभेद) श्री २५/८/२०१४ उपजिलाधिकारी २५/८/२०१४ अध्यक्ष २— श्री २५/८/२०१४ उप प्रभागीय वनाधिकारी २५/८/२०१४ सदस्य ३— श्री ठाकुर एस-एवेन सहायक समाज कल्याण अधिकारी २५/८/२०१४ सम्पदस्य सचिवकल्याण अधि ४— श्री जगद्दीप बी०डी०सी० क्षेत्र २५/८/२०१४ विं० ख० सदस्यासेन (अल्मोड़ा)

जोगासिद

सदस्य

सेत्र पंचायत वासी
बी० मिक्यासेन (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी

की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

सरपटा-चुड़ाली-कोटा वार्ड

परियोजना हेतु ०.५३७ हे० वन

भूमि

सरपटा-चुड़ाली-कोटा वार्ड नो०२१ अल्मोड़ा

२०/८/२०१४ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, २५/८/२०१४ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधिक नियम के स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

16 D

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र परियोजना के निर्माण हेतु
हेतु
वन भूमि 0.837 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद
.....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, रामेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी,
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद
.....

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग। (8.50 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग (8.50 किमी.) के निर्माण हेतु ५३७ है ० वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

20/-
जिलाधिकारी

169

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date 04-12-2014.....at time.....at Almora. in which application claiming rights of Basot, chanuli area measuring hect. for the Construction of Sarpata- chanuli - kota Basot motar road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

YKWS
04.12.14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा।

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला सभापति कल्याण विकारी
अल्मोड़ा।

1.6. H

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.537 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलसोडा

व्यवहार
04.12.14

जिला अधिकारी
बलसोडा. Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

16 F

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :.....

Dated:.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 0.53.7 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sarpathi chanuli kota Basat metar road.

(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chanuli village(s) in Bhikujian Tehsil.

It is further Certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.53.7 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

महानगरीकरण विभाग
Tehsildar

स.प्रभा.विकास,
विविधारण (शल्मोहा)

०५/१२/२०१४
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
D.M.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण विभाग
बल्लोड़ा